हिन्दुस्तान 14
लखनऊ •शनिवार •31 जनवरी 2015

Media/LKO/025/2015

यूपी की चीनी मिलों का आर्थिक संकट गहराया

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

दामों से संकट

- सरकार से यूपी इस्मा ने मदद की लगाई गुहार
- गन्ना आपूर्ति के बाद किसानों को भुगतान में देरी पर लग रहे ब्याज से मुक्ति मांगी

खुले बाजार में चीनी के दाम लगातार गिरते जाने और चालू पेराई सत्र में लागत भी न निकल पाने के चलते प्रदेश की निजी चीनी मिलों का संकट और गहरा गया है।

उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन (यूपी इस्मा) ने इस बाबत शुक्रवार को प्रदेश के प्रमुख सचिव गन्ना एवं चीनी उद्योग राहुल भटनागर को एक पत्र देकर मदद की गुहार लगायी है। साथ ही लागू पेराई सत्र में मिलों को गन्ना आपूर्ति के चौदह दिन बाद किसानों को किए जाने वाले भुगतान में देरी पर लग रहे ब्याज से मुक्ति मांगी गयी है।

इसी क्रम में प्रदेश सरकार से यह भी फरियाद की गयी है कि चूंकि इस वक्त गन्ने की पेराई और चीनी बनाने में जो लागत आ रही है, उसे देखते हुए 185 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गन्ना मूल्य का भुगतान चीनी मिलें नहीं कर पा रही हैं। लिहाजा, चीनी मिलों को इस वक्त 240 रुपए प्रति क्विंटल के बजाए पहली किस्त के रूप में किसानों को 200 रुपए प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य भुगतान करने की इजाजत दी जाए। यूपी इस्मा के प्रवक्ता दीपक गुप्तारा ने 'हिन्दुस्तान' को बताया कि प्रदेश की निजी चीनी मिलों पर इस वक्त कुल 2480.25 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य बकाया हो चुका है। इसमें से 2455.38 करोड़ मूल और 24.97 करोड़ रुपए ब्याज बकाया हो चुका है।

उधर निजी चीनी मिलों के संगठन इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि चालू पेराई सत्र में अब तक पूरे देश में किसानों को देय गन्ना मूल्य का बकाया करीब 11000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। संगठन के प्रवक्ता संजय बनर्जी के अनुसार चीनी का दाम पिछले तीन वर्षों में सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। संकट लगातार गहराता जा रहा है। ऐसे में अब चीनी मिलों के सामने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य 220 रुपए प्रति क्विंटल भी अदा न कर पाने की नौबत आ गयी है।